निवेश क्रियान्वयन का काम राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ के हवाले

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश के क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार के नेतृत्व में राज्यस्तरीय लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। इस सेक्टर के समग्र विकास के लिए राज्यस्तरीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना पर काम होगा। इसके लिए आलोक कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना पर काम की कमान आलोक को

योजना के अंतर्गत उद्योगों की सुविधा के लिए आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण सुविधाओं का विकास होगा। प्रदेश का लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ केंद्र सरकार के लॉजिस्टिक्स डिवीजन से समन्वय करेगा। शासन के कई विभाग इस सेल के प्रमुख सदस्य होंगे। केंद्रीय एजेंसियों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आदि के नोडल अधिकारी सेल में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। योजना की प्रगति और कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति होगी। वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अब तक करीब 438 करोड़ रुपये के छह निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आलोक ने बताया कि मजबूत लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना के लिए 6 मापदंडों पर कार्य होगा। इसमें प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था में सुगमता, अवस्थापना की गुणवत्ता, सेवा प्रदाताओं की गुणवत्ता, कार्गो परिवहन की सुरक्षा, विनियामक प्रक्रिया की दक्षता तथा राज्यस्तरीय समन्वय एवं सुविधा शामिल है। ब्यूरो

प्राधिकरण सुविधाएं व सहूलियत बढ़ा रहे

वर्ष 2018 में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति घोषित की गई। इसके बाद कम लागत और कम परिवर्तन शुल्क पर भूमि सुलभ कराने के लिए भूमि उपयोग नीति में संशोधन किया गया। अब विकास प्राधिकरण लॉजिस्टिक्स पार्क और इकाइयों के लिए औद्योगिक भूमि-उपयोग परिवर्तन शुल्क लागू करने के लिए अपने जोनिंग नियमों, मास्टर प्लान और उपनियमों में संशोधन कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स पार्क अब 50 की जगह 25 एकड़ में ही स्थापित हो सकता है।

दादरी देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन ग्रेटर नोएडा के दादरी में है। इसे देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य में खोड़ाकी और वाराणसी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स व ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं।

आत्मनिभर भारत के निर्माण तथा कोविड-19 महामारी के दौरान सप्लाई चेन में अवरोधों को ध्यान में रखकर एकीकृत योजना तैयार की गई है। इससे लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन के विकास के लिए समन्वित व केंद्रित कार्यवाही हो सकेगी। **– सतीश महाना,** मंत्री औद्योगिक विकास